श्रीमान अमित जोगी जी,
अध्यक्ष, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ (जे),
रायपुर (छ.ग.) ।

दिनांक : 20.08.2020

आदरणीय महोदय,

विषय :एल.आई.सी. को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करते हुये इसमें सरकारी भागीदारी को कम किया जाना ।

उपरोक्त मुद्दे पर दिनांक 14 जुलाई, 2020 को हमारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे द्वारा आपके नाम प्रेषित पत्र का संदर्भ देते हुये हम आपको पुनः पत्र लिख रहे हैं क्योंकि इस विषय पर आपका हस्तक्षेप अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है । सरकार इस मुद्दे पर उस वक्त तेजी से आगे बढ रही है जब संसद का सत्र चालू नहीं है ।

सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम में अपने स्वामित्व के कुछ भाग को बेचने की प्रक्रिया आरंभ किये जाने की रिपोर्ट से हम काफी परेशान हैं । वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) द्वारा कथित तौर पर ट्रांजिक्शन पूर्व सलाहकारों को नियुक्त करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है जो DIPAM को LIC के IPO संबंधी प्रक्रिया में सहायता करेंगे । इस प्रकार सरकार ने देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित सार्वजनिक वित्तीय संस्थान में अपनी हिस्सेदारी के एक भाग को बेचने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है ।

LIC को स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध किये जाने के पक्ष में दिये जा रहे तर्क पूर्णतः तथ्य रहित है । LIC एक्ट पारदर्शी व कुशल बोर्ड द्वारा प्रबंधित संस्थान है । यह प्रत्येक तिमाही में आंकडों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है । यह प्रत्येक माह अपने कार्यकलापों की रिपोर्ट नियंत्रक IRDA को प्रस्तुत करता है । यह अपना लेखा–जोखा जॉच हेतु संसद में पेश करता है तथा जनता के प्रति जवाबदेह है । भारतीय अर्थव्यवस्था में LIC सबसे बडी निवेशक है । इसलिये सूचीबद्धता के जरिये LIC की बाजार के फंड तक पहुंच में सहायता करने का कारण तर्कसंगत नहीं है । LIC प्रतिवर्ष 3.5 लाख करोड रू. से 4 लाख करोड रू. का भारी भरकम निवेश योग्य फंड उत्पन्न करती है इसलिये LIC को फंड हेतु बाजार तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

संसद के एक अधिनियम के माध्यम से LIC का निर्माण हुआ था, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा कदम जो पॉलिसीधारकों एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालेगा– सरकार द्वारा संसद में पूर्ण बहस किये बिना ही आगे बढाया जा रहा है । सन् 1956 में LIC की शुरूआत के साथ ही इसके द्वारा देश के औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किये जाने तथा राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में निरंतर दिये जा रहे योगदान से आप परिचित हैं ।

.....2.....

हम यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि LIC का विकास, उसका विस्तार एवं पालिसीधारकों की संख्या एवं दावों के भुगतान के आधार पर विश्व के सबसे बडे बीमाकर्ता के रूप में उसका उदय, यह सब पूरी तौर से आंतरिक रूप से उत्पन्न संसाधनों के माध्यम से किया गया है । सरकार द्वारा सन् 1956 में दी गई 5 करोड रूपयों की आरंभिक पूंजी जिसे नियंत्रणकारी प्रावधानों के चलते सन् 2011 में बढाकर 100 करोड रू. किया गया था । इसके अतिरिक्त कोई योगदान नहीं दिया गया । इतनी अल्प पूंजी के आधार पर आज LIC अपने 32 लाख करोड रूपयों से भी अधिक की संपत्ति को प्रबंधित कर रही है । चूंकि यह विस्तार पॉलिसीधारकों से एकत्रित किये गये धन के माध्यम से हुआ है, LIC ने एक पारस्परिक आपसी लाभकारी समाज की तरह कार्य किया है । LIC में हिस्सेदारी के एक अंश को बेचने का निर्णय लेते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी की गई है । 245 निजी बीमाकर्ताओं का अधिग्रहण कर जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य छोटी बचतों को एकत्रित कर उन्हें आधारभूत संरचना हेतु दीर्घकालीन निवेश में बदलना तथा उसी समय पालिसीधारकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हुये आकर्षक वापसी को सुनिश्चित करना था । LIC प्रशंसनीय रूप से इन उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए कार्य कर रही है । सरकार द्वारा हिस्सेदारी बेचे जाने से अंततः निजीकरण को बढावा मिलेगा जो इन उद्देश्यों का खात्मा करेगा । इस कदम से जनता का धन जनता के कल्याण हेतु की अवधारणा शेयरधारकों हेतु अधिकाधिक मुनाफा के रास्ते पर चली जायेगी । यह न तो LIC के 40 करोड पालिसीधारक के हित में है और न ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में । प्रख्यात अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यापक रूप से यह स्वीकार किया गया है कि घरेलू बचत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है तथा विदेशी पूंजी घरेलू बचत के लिये एक खराब विकल्प है । उस स्थिति में जब देश के विकास हेतु विशाल संसाधनों की आवश्यकता है, सरकार को आंतरिक एवं महत्वपूर्ण घरेलू बचतों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहिये ।

इस सर्वोत्तम वित्तीय संस्थान के निर्माण में अपना असाधारण योगदान प्रदान करने वाले LIC के कार्यबल के पास सरकारी हिस्सेदारी के एक भाग की बिक्री के प्रस्ताव का विरोध करने के वैध एवं न्यायसंगत कारण मौजूद है । LIC को 100 प्रतिशत सरकारी नियंत्रण में बनाये रखा जाना चाहिये । यह ऐतिहासिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि केवल सरकार द्वारा नियंत्रित जनता की बचत से ही राष्ट्रीय विकास को प्रणालीबद्ध किया जा सकता है । घरेलू बचतों पर निजी क्षेत्रों का नियंत्रण निजी मुनाफे को अधिकतम करने का कार्य ही करेगा । इस तथ्य पर विचार करते हुये कि हमारा देश अब भी एक कम आय वाला देश है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीमा क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में बना रहे जिससे क्रास सब्सिडी के माध्यम से गरीब व कमजोर तबके की बीमा आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके । सरकारी हिस्सेदारी बेचने का हमारा विरोध पक्षपातपूर्ण न हो कर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हितों पर आधारित है ।

.....3.....

हम पुनः जोर देना चाहेंगे कि LIC की इक्विटी बेचने का कदम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय जनता के कमजोर तबकों को बुरी तरह से प्रभावित करेगा । कमजोर तबकों को बीमा उपलब्ध कराने के सामाजिक उद्देश्यों को एक गंभीर झटका होगा । गैर लाभदायक ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा के विस्तार के लक्ष्य को हानि पहुंचेगी । अतः LIC के चरित्र को अस्त–व्यस्त करने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय समाज के गरीब तबकों के हितों को नुकसान होगा ।

इन परिस्थितियों में हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि LIC में सरकारी हिस्सेदारी कम किये जाने के खिलाफ जारी हमारे संघर्ष को अपना समर्थन दें एवं 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली LIC को बनाये रखने के लिये सरकार पर दबाव निर्मित करें ।

धन्यवाद,

आपका विश्वासपात्र

(सुरेन्द्र शर्मा)
महासचिव